दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादकः सत्येन्द्र सिंह

सभी से वोट की अपील : ललित ठुकराल.. P-8

वर्ष : 15 ▸ अंक : 4 ▸ गाजियाबाद, अप्रैल, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08+04 (ऑफ यूवी इंडिया न्यूज) E-mail : udyogviharnp@gmail.com

डॉ. महेश शर्मा एवं जनरल वी.के. सिंह को फिर मिला जनता का विश्वास

इतने बड़े कद के प्रत्याशी के आगे कांग्रेस और सपा, बसपा के प्रत्याशी बौने नजर आये

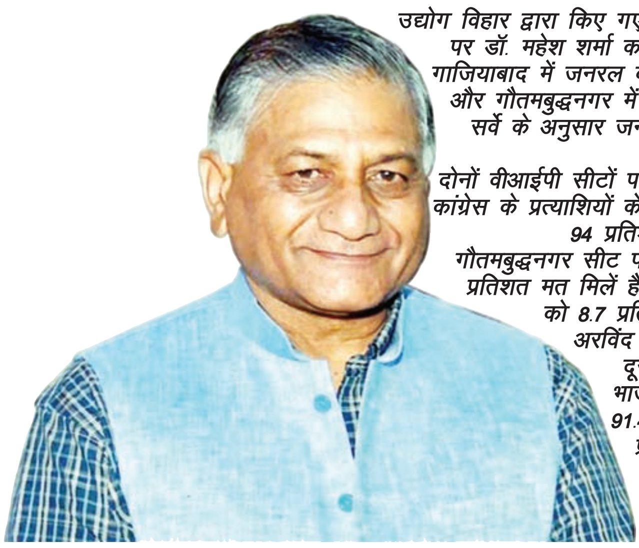

उद्योग विहार द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार जनता गौतमबुद्धनगर सीट पर डॉ. महेश शर्मा को ही पुनः सांसद देखना चाहती है। वहीं गाजियाबाद में जनरल वी.के.सिंह के पक्ष में माहौल है। गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में चुनाव के ठीक दस दिन पहले किए गए सर्वे के अनुसार जनता का रूझान भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है।

दोनों वीआईपी सीटों पर तीन प्रमुख दलों भाजपा, सपा–बसपा एवं कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए सर्वे करवाया गया, जिसमें भाजपा को 94 प्रतिशत से ऊपर मत दिया गया।

गौतमबुद्धनगर सीट पर भाजपा के डॉ. महेश शर्मा को जहां 85.2 प्रतिशत मत मिलें हैं। वहीं सपा–बसपा को प्रत्याशी सतवीर नागर को 8.7 प्रतिशत मत मिले है तथा कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. अरविंद सिंह चौहान को 6 प्रतिशत मत मिले हैं।

दूसरी तरफ गाजियाबाद सीट पर भाजपा के जनरल वी.के. सिंह को 91.4 प्रतिशत तथा सपा–बसपा के प्रत्याशी सुरेश बंसल को एवं कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को बराबर–बराबर 4.2 प्रतिशत मत मिले हैं।

भाजपा का जनाधार अगर बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश की जनता बाकी सारे मुद्दों को किनारे रखकर सिर्फ विकास और देश की सुरक्षा को महत्व दे रही है। इस बार होने वाले चुनाव में निर्णायक मतदाता युवा वर्ग 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भाजपा सरकार की उपलब्धियों के अनुसार उसे स्पष्ट लाभ होता नजर आ रहा है। जिसमें से प्रमुख उपलब्धियां–

–'आयुष्मान भारत' योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद परिवार लगभग 50 करोड़ लाभार्थी प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का ईलाज करा सकेंगे।

–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की पूर्ण निर्मित लंबाईः 1 लाख 99 हजार किलोमीटर से अधिक।

–उज्जवला योजना के तहत लगभग 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किये गए हैं।

–स्वच्छ भारत के तहत निर्मित घरेलू शौचालयों की संख्या : 9 करोड़ 77 लाख से ज्यादा।

–उजाला योजना के तहत वितरित एल.ई.डी बल्ब : लगभग 33 करोड़ 34 लाख।

–'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के तहत किसानों को सम्मान स्वरूप हर साल 6000 रूपये की राशि सीधा उनके खाते में जमा की जाएगी। किसान परिवारों को इसकी पहली किश्त उनके खाते में पहुंचा दी गयी है।

–सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए मौजूदा मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक कर दिया गया है।

–आर्थिक तौर पर पिछड़े एवं सवर्णो (सामान्य वर्ग) को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग दिया जाएगा।

–प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण निर्मित घरों की संख्या : 1 करोड़ 53 लाख एवं सौभाग्य योजना के तहत घरों की संख्या : लगभग 2 करोड़ 52 लाख।

–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या : 14 करोड़ 24 लाख।

–केंद्र सरकार द्वारा हर गांव को विद्युतीकृत कर दिया गया है। अब ऐसा कोई गांव नहीं जो बिजली से रौशन ना हो।

–'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' के अंतर्गत गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को 3000 रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

–फसलों की एमएसपी लागत से 50 फीसदी अधिक पर निर्धारित की जाएगी, किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज छूट (सब्सिडी) दी जाएगी एवं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी।

कांग्रेसी की युवा प्रत्याशी डॉली शर्मा ने एमबीए किया हुआ है और उनका ऑनलाइन का कारोबार है। काफी समय से सामाजिक कार्य करने के साथ ही सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं। 2017 में निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव लड़कर उन्होंने काफी सुर्खियां बंटोरी थी। उनके पिता नरेन्द्र भारद्वाज पुराने कांग्रेसी हैं। मगर वर्तमान सर्वे में कांग्रेस तीसरे स्थान पर आ रही हैं।

गौतमबुद्धनगर सीट से सतवीर नागर सपा–बसपा–रालोद गठबंधन से उम्मीदवार हैं। मायावती ने गुर्जर प्रत्याशी को उतारकर इस सीट पर एक बड़ा दांव खेला है। बसपा ने पहले वीरेन्द्र ढाढा और संजय भाटी का टिकट काटकर सतवीर नागर को उम्मीदवार बनाया है। जिससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना उनको करना पड़ेगा। सर्वे में उनका स्थान दूसरे नंबर पर है।

सुरेश बसंल गाजियाबाद की राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। 2012 में बसपा की टिकट पर गाजियाबाद से विधानसभा पहुंचे थे। मगर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अतुल गर्ग से हार गए थे। गाजियाबाद सीट सपा के खाते में आने पर बसपा ने उन्हें सुरेन्द्र मुन्नी का टिकट काटकर सपा ज्वाइंन करवाई है। अब वे सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। सर्वे में सपा–बसपा–रालोद गठबंधन दूसरे स्थान पर आ रहा है।

गौतमबुद्धनगर सीट से डॉ. अरविन्द सिंह चौहान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वे भाजपा एमएलसी जयवीर सिंह के बेटे हैं। उनके पिता ने उनसे सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ दिया है। क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। अभी वे राजनीति के इतने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हैं और उनको महेश शर्मा जैसे कद्दावर नेता से मुकाबले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वे में उनका स्थान तीसरे नंबर पर है।

ईएसआई अस्पताल को 30 नए चिकित्सक मिलेंगे

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

साहिबाबाद। राजेंद्र नगर स्थित ईएसआई अस्पताल को अगले सप्ताह 30 नए चिकित्सक मिलेंगे। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। 15 फरवरी को अस्पताल के उद्घाटन के बाद से ही डॉक्टरों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि 2016 में यूपी सरकार से अस्पताल का हस्तांतरण होने के बाद से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी चल रही थी। अस्पताल की इमारत का काम पूरा नहीं होने से संविदा पर रखे गए डॉक्टरों से चिकित्सकीय सुविधाएं ली जा रहीं थी। **शेष पृष्ठ 6 पर**

फर्जी खबरों के बारे में आगाह करेगा वाट्सएप

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। देश में आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मैसेजिंग एप वाट्सएप ने नई पहल की है। वाट्सएप ने मंगलवार को 'चेकपॉइंट टिपलाइन' का अनावरण किया, जिसकी मदद से यूजर फर्जी खबरों की पड़ताल कर सकेंगे। फर्जी और गुमराह करने वाली खबरों पर नकेल की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। वाट्सएप ने बताया, भारतीय स्टार्टअप फर्म प्रोटो ने इस टिपलाइन को विकसित किया है। इसकी मदद से चुनाव के दौरान अफवाहों और फर्जी खबरों को लेकर डाटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डाटाबेस चेकपॉइंट की तरह काम करेगा। इस प्रोजेक्ट को तकनीकी मदद वाट्सएप की तरफ से मिलेगी। कंपनी ने बताया कि भारतीय यूजर अब वाट्सएप नंबर, 91–9643000888 पर चेकपॉइंट **शेष पृष्ठ 6 पर**

देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 26 फीसदी हुई: रिपोर्ट

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में पिछले कुछ सालों के दौरान गिरावट देखने को मिली है. डिलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 36.7 प्रतिशत थी जो 2018 में गिरकर 26 प्रतिशत पर आ गयी. डिलॉयट ने 'भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण रिपोर्ट में कहा कि असंगठित क्षेत्र में 95 प्रतिशत यानी 19.5 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो या तो बेरोजगार हैं या उन्हें काम के बदले पैसा नहीं मिलता है. **शेष पृष्ठ 6 पर**

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING: U.P. GENERAL W.E.F. 01/04/19 TO 30/09/2019 BASIC +DA	U.P. ENGG. BELOW 500 W.E.F. 01/02/19 TO 31/07/2019 BASIC +DA	U.P. ENGG. ABOVE 500 W.E.F. 01/02/19 TO 31/07/2019 BASIC +DA	DELHI MINIMUM WAGES: MINIMUM WAGES W.E.F. 10/1/2018 BASIC+DA	RAJASTHAN MINIMUM WAGES: MINIMUM WAGES W.E.F. 1/1/2018 BASIC+DA	GUJRAT MINIMUM WAGES: MINIMUM WAGES W.E.F. 01/04/2018 TO 30/09/2018 ZONE-I BASIC+DA	GUJRAT ZONE-II BASIC+DA	PUNJAB MINIMUMWAGES: MINIMUMWAGES W.E.F. 3/1/2018 BASIC+DA	HARYANA MINIMUMWAGES: MINIMUMWAGES W.E.F. 1/1/2018 BASIC+DA	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES: MINIMUMWAGES W.E.F. 01-10-2018 TO 31-03-2019 BASIC+DA
UN SKILLED	8021.52	9380.31	9834.20	14000	5338.00	8117.20	7909.20	7852.17	8227.4	8331
SEMISKILLED	8823.67	10300.69	10817.62	15400	5798.00	8325.20	8117.20	8632.17	*	8924
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	9883.90	11435.41	11801.04	16962	6058.00	8559.20	8325.20	9529.17	*	9518
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7358.00	*	*	10561.17	11266.23	*

नौकरी बदलने पर खुद-ब-खुद होगा ईपीएफ ट्रांसफर, ईपीएफओ कर रहा तैयारी

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ राशि स्थानांतरण करने का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी. इस प्रक्रिया को स्वचालित बनाने पर काम चल रहा है. श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अभी ईपीएफओ के सदस्यों को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) रखने के बाद भी ईपीएफ स्थानांतरण करने के लिये अलग से अनुरोध करना पड़ता है. ईपीएफओ को हर साल ईपीएफ स्थानांतरण करने के करीब आठ लाख आवेदन मिलते हैं.

श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''ईपीएफओ प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर ईपीएफ के स्वतः हस्तांतरण पर काम कर रहा है. सभी सदस्यों के लिये सह सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है.'' अधिकारी ने कहा, ''ईपीएफओ ने कागजविहीन संगठन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनी परिचालन प्रणाली के अध्ययन का काम सी–डैक को दिया है. अभी 80 प्रतिशत कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं. लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वतः हस्तांतरण महत्वपूर्ण है.''

> ❑ नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वतः हस्तांतरण होने पर सदस्यों को काफी लाभ होगा क्योंकि यूएएन एक बैंक खाते की तरह हो जाएगा: वरिष्ठ अधिकारी

अधिकारी ने कहा कि जैसे ही नये नियोक्ता मासिक ईपीएफ रिटर्न दायर करेंगे जिसमें नये कर्मचारी का यूएएन भी शामिल होगा, वैसे ही पहले के ईपीएफ योगदान और उसपर अर्जित ब्याज का स्वतः हस्तांतरण हो जाएगा. उन्होंने कहा, ''नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वतः हस्तांतरण होने पर सदस्यों को काफी लाभ होगा क्योंकि यूएएन एक बैंक खाते की तरह हो जाएगा. इससे कोई अंत नहीं पड़ेगा कि सदस्य जगह या नियोक्ता बदलता है, ईपीएफ में वह अपना योगदान यूएएन के जरिये हासिल कर सकेंगे. यह कर्मचारियों के पूरे जीवन के दौरान लागू रहेगा.''

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
❖ LABOUR LAWS ❖ HR MANAGEMENT
❖ PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖ SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)
http://www.legalipl.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

TAKSHAK MANAGEMENT INDIA PVT LTD
❖ EVENTS MANAGEMENT
❖ PR MANAGEMENT
❖ ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर सीट पर भाजपा पहले पायदान पर

गाजियाबाद

मुख्य मुकाबला : जनरल वी.के.सिंह (भाजपा), सुरेश बंसल (सपा) और डोली शर्मा (कांग्रेस) उम्मीदवार लेकिन असली लड़ाई भाजपा और सपा के बीच।

लोकसभा चुनाव 2014 : भाजपा के जनरल वी.के.सिंह ने कांग्रेस के राज बब्बर को पांच लाख से अधिक मतों से हराया था। लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना में भाजपा आगे।

विधानसभा चुनाव 2017 : सभी पांच विधानसभा सीटें लोनी, मुरादनग, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना में भाजपा ने कब्जा जमाया।

प्रमुख मुद्दे : कानून–व्यवस्था, रोजगार, बड़े आवासीय प्रोजेक्ट में फंसे आवंटी, सफाई व्यवस्था।

कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का समर्थन करने वाले भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की अन्य लोकसभा सीटों पर सक्रियता को लेकर संशय बना हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में असंतोष भी है। गौतमबुद्धनगर लोकसभा सीट से भाजपा के विधान परिषद सदस्य ठाकुर जयवीर सिंह के बेटे अरविंद सिंह चौहान को कांग्रेस का टिकट मिलने से स्थानीय नेता नाराज हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुराज सिंह कहते हैं, ''2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गया था, ठीक वैसा ही इस बार भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए।''

केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं को बयानों से बचने को कहा है जिससे भाजपा को मुसलमान विरोधी भावनाएं भड़काने का मौका ना मिले। मेरठ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर मनोहर सिंह कहते हैं, ''2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान नेताओं के विवादास्पद बयानों ने हिंदू मतदाताओं को इनके खिलाफ एकजुट किया था जिसका फायदा भाजपा को मिला था। इस बार मुसलमान नेताओं के संयम बरतने के कारण पिछले चुनावों जैसी स्थिति नहीं है।'' वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में हुए पहले चरण का चुनाव जिस पार्टी ने जीता वही अंत तक आगे बनी रही। इसीलिए इस इलाके का चुनाव बेहर महत्वपूर्ण हो गया है।

गौतमबुद्धनगर

मुख्य मुकाबला : डॉ. महेश शर्मा (भाजपा), सत्यवीर नागर (बसपा), और अरविंद सिंह चौहान (कांग्रेस) मुख्य दलों के उम्मीदवार, भाजपा के सामने बसपा के गुर्जर–दलित–मुसलमान गठजोड़ की कठिन चुनौती।

लोकसभा चुनाव 2014 : भाजपा के डॉ. महेश शर्मा ने सपा के नरेंद्र भाटी को दो लाख से अधिक मतों से हराया था। नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा पर भाजपा आगे।

विधानसभा चुनाव 2017 : सभी पांच विधानसभा सीटें नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा भाजपा ने जीती।

प्रमुख मुद्दे : कानून–व्यवस्था, हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डरों के चंगुल में फंसे आवंटी, रोजगार।

गाजियाबाद के बड़े गन्ना किसान और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता मांगेराम त्यागी कहते हैं, ''गन्ना किसानों का बकाया भुगतान लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा है। भाजपा सरकार के लिए किसानों की नाराजगी से निबटना आसान नहीं होगा।'' गन्ना किसानों में बढ़ते असंतोष और इससे होने वाले चुनावी नुकसान को रोकने के लिए भाजपा ने यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर को आगे किया है। दोनों नेता किसानों के बीच बैठकें करके भाजपा सरकार में गन्ना किसानों की बेहतरी के लिए किए गए कार्य गिना रहे हैं। सुरेश राणा कहते हैं, ''पश्चिमी यूपी की 55 चीनी मिलों में पिछले चार वर्षों का भुगतान भाजपा सरकार ने कराया है। अब करीब चार माह का भुगतान ही बकाया है जिसे पेराई सत्र खत्म होने से पहले पूरा कर दिया जाएगा।'' गन्ना किसानों के लिए सरकार की घोषणाएं और लंबित भुगतान के मसले को भुनाने में जुटे विपक्ष के लिए पश्चिमी यूपी में पहले चरण का चुनाव रोचक हो गया है, जिसमें भाजपा के सामने वर्ष 2014 की एकतरफा जीत को बचाए रखने की बेहद कठिन चुनौती है।

जनरल वी.के.सिंह की उपलब्धियाँ

- ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण, जिससे मेरठ की दूरी 45 मिनट में व गुडगांव की 75 मिनट में संभव।
- मेट्रो का जाल नया बस अड्डा (शहीद स्थल) से दिलशाद गार्डन चालू हो गया है तथा नोएडा सेक्टर–62 से इंदिरापुरम होते हुए मोहननगर को जोड़ने के लिए कार्य चालू है।
- गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डे का शुभारंभ आम जनता के लिए किया गया। जिसमें यात्रीगण मात्र 2500 रूपए में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं।
- एलिवेटेड रोड़ का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक कम हुआ है और लोगों को दिल्ली पहुंचने में मात्र 12 मिनट का समय लगता है।
- गाजियाबाद में रैपिड रेल के प्रोजेक्ट पर कार्य चालू हो गया है। रैपिड रेल के बनने से दिल्ली से गाजियाबाद एवं मेरठ जाने में काफी सहुलियत हो जाएगी।
- एनएच–24 (वर्तमान में एनएच–9) पर यूपी गेट से मेरठ तक मेरठ एक्सप्रेस–वे का कार्य लगभग पूर्ण होने को है, जिसके बनने से दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 45 मिनट में तय की जा सकेगी।
- गाजियाबाद में बुनकर मार्ट की स्थापना की जा रही है जिसकी वजह से जहां बुनकरों को फायदा होगा। वहीं उद्योग धंधों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद को प्रथम स्थान दिया गया है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से अग्रसर होने वाला जिला बना है। जहां भारत वर्ष में इसका स्थान 11वां है। वहीं उत्तरप्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
- गाजियाबाद को सिटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स का दर्जा ओडीओपी के तहत दिया गया है। इससे गाजियाबाद में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार की दिशा में यह एक शानदार कदम है।

डॉ. महेश शर्मा की उपलब्धियाँ

- जेवर, अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर को मिला।
- ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण, जिससे मेरठ की दूरी 45 मिनट में व गुडगांव की 75 मिनट में संभव।
- मेट्रो का जाल बॉटेनिकल गार्डन से मैजेंटा मेट्रो लाइन की शुरूआत। ग्रेटर नोएडा, जेवर, फरीदाबाद, गाजियाबाद एवं नोएडा एक्सटेंशन तक।
- पासपोर्ट सेवा केंद्र (नोएडा) नोएडा सेक्टर, 19 में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ।
- सांस्कृतिक भवन ग्रेटर नोएडा, परी चैक में 25 एकड़ भूमि में शुभारंभ। (परियोजना लागत: 289 करोड़)
- भारतीय पाक कला संस्थान सेक्टर 62, (पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत) नोएडा में शुभारंभ। (परियोजना लागत: 98 करोड़)
- विद्युत परियोजना खुर्जा 1201 एकड़ भूमि में स्वीकृति। 25000 रोजगार अवसर। (परियोजना लागत: 11000 करोड़)
- महामाया फ्लाईओवर को चिल्ला रेगुलेटर से जोड़ता एलिवेटेड मार्ग (परियोजना लागत: 650 करोड़)
- बॉटेनिकल गार्डन नोएडा के सेक्टर 38 में 164 एकड़ में बनाया गया। (परियोजना लागत: 400 करोड़)
- ओखला पक्षी विहार का पुनर्विकास कार्य 300 एकड़ में किया गया कार्य। (परियोजना लागत: 70 करोड़)
- हैबिटेट सेंटर 25 एकड़ भूमि में सेक्टर 94 में शुभारम्भ।
- राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत (परियोजना लागत: 110 करोड़)
- गौतमबुद्धनगर को सिटी ऑफ अपैरल का दर्जा मिला और अपैरल पार्क 280 एकड़ में बनाने की मंजूरी मिली। जिसपर 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बनने से लगभग पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। वहीं 70 प्रतिशत रोजगार तो सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा।

डॉ. महेश शर्मा ने गौतमबुद्धनगर जिले में पिछले साढ़े चार वर्षों में काफी कार्य किया है और इस सर्वे में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि जनता सिर्फ विकास चाहती है तथा यह चाहती है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताऐं पूरी हों। हालांकि की अभी बहुत कुछ करने की आवश्यता है। लेकिन यदि इस बार भी केंद्र में भाजपा की सरकार पुनः आती है तो सर्वे के अनुसार जैसा कि लोगों को विश्वास है कि देश तरक्की करेगा और लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास कार्य में भी इजाफा होगा।

यह बात तो स्पष्ट है कि इस बार मतदाता स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर देशहित की सोच रहा है। तभी उसने भाजपा के देशहित में किए गए फैसलों को वरीयता दी है। चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर अंतरिक्ष में सेटेलाइट को मिसाइल द्वारा ध्वस्त कर देना।

'मैं भी चौकीदार' को जनता ने सकारात्मक तरीके से लेते हुए खुद को हर क्षेत्र में चौकीदार मानते हुए जिस तरह अपने–अपने क्षेत्र की रक्षा करने का संकल्प लिया है। यह कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। इस अभियान से कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया है कि उसके प्रवक्ताओं को चौकीदार शब्द बोलने में भी डर लग रहा है। अगर आप हाल ही के कांग्रेस के किसी भी बयान पर गौर करेंगे तो आप बयानों में से चौकीदार शब्द नदारद पायेंगे।

वहीं जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि वे आज 11:45 पर एक बड़ी घोषणा करेंगे तो विपक्षी खेमे में हलचल मच गई थी। डर का आलम यह था कि सभी विपक्षी नेता अपनी मीटिंग, अपनी रैली एवं अपना घोषणा–पत्र जारी करने का कार्यक्रम रोककर सांसे थामकर टेलीविजन के सामने 11:30 बजे से ही जम गए थे।

शेष पृष्ठ पांच पर

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

Editorial

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, अप्रैल, 2019

सम्पादकीय

वोट का विवेक

सत्येन्द्र सिंह

देश भर में राज्यों की विधानसभाओं या फिर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं के अलग-अलग हिस्से को प्रभावित करने और उनसे किसी खास उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी को वोट देने की अपील करने का चलन कोई नया नहीं है। अगर इस तरह की अपील सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर आधारित हो और जनता के सशक्तिकरण को लक्षित हो, तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर किसी एक धार्मिक पहचान के नाते लोगों को किसी खास पार्टी को वोट देने की अपील जारी की जाती है तो इसके राजनीतिक संदर्भ एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि देश में कहीं भी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव आने के साथ कुछ धर्मगुरुओं की अहमियत बढ़ जाती है और अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता उनसे संपर्क साध कर लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील जारी करने की गुजारिश करते देखे जाते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है कि इन धर्मगुरुओं का अपने अनुयायी तबकों पर खासा असर होता है और उनके कहने के मुताबिक कुछ हद तक लोगों के वोट डालने के फैसले भी प्रभावित होते देखे गए हैं। इस लिहाज से देखें तो पिछले कुछ दशकों के दौरान हमारे देश में मुसलिम समुदाय के लिए कुछ स्थानीय धर्मगुरुओं या फिर उलेमाओं की ओर से किसी पार्टी को वोट देने की अपील जारी करने की खबरें सुर्खियों में रही हैं। यह अलग बात है कि इस तरह की अपीलों का वास्तव में मुसलिम आम जनता पर कितना असर पड़ता है। इसके बावजूद मुसलिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे धर्मगुरु या फिर उलेमा समय-समय पर उनके लिए किसी मसले पर फरमान सुनाने से लेकर वोट देने तक की अपील करते रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार हुआ है, जागरूकता बढ़ रही है, राजनीतिक चेतना का विस्तार हो रहा है, वे अपने धर्म के किसी गुरु के कहने भर से वोट देने में विश्वास करना तेजी से कम कर रहे हैं। पिछले कई चुनावों के दौरान यह साफतौर पर देखा गया है कि अब लोग स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर देशहित को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर गौर करते हैं, उनमें देश का, समाज का और अपना हित-अहित देखते हैं और उसके बाद किसी राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार को वोट देने का फैसला करते हैं। जाहिर है, यह हमारे देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि किसी धर्मगुरु के जरिए वोट डालने की अपील कराने का चलन केवल मुसलिम समुदाय के बीच सीमित नहीं रहा है। हिंदू धर्म की पहचान के तहत खड़े हुए कई पंथ और मत के वैसे गुरुओं और बाबाओं से भी राजनीतिक दल अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कराने की कोशिश करते देखे गए हैं, जिनका अपने अनुयायियों पर काफी असर होता है। यों यह अपने आप में एक अफसोसजनक स्थिति है कि किसी भी धर्म या पंथ में विश्वास रखने वाले समुदाय को एक वोट बैंक की तरह देखा जाए और उनका वोट हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं से जुड़े वैसे मुद्दों पर जोर दिया जाए, जिनसे लोगों के जीवन-स्तर में छाई जड़ता तो नहीं टूटती, उल्टे धर्म के नाम पर उनका भावनात्मक शोषण संबंधित धर्म के गुरु या बाबा के जरिए राजनीतिक दल करते हैं। इससे न तो धर्म मजबूत होता है, न समाज।

क्षेत्रीय ताकतों को कांग्रेस का उभार पसंद नहीं आ रहा, इसलिए दूरी बना रहे हैं

कर्नाटक में पिछड़ने के बावजूद भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखने और वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में मिली सफलता से एक बार लगने लगा था कि आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है। चाहे चुनाव आयोग द्वारा आम चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने लंगर लंगोट कसने शुरू कर दिए थे परंतु राजनीतिक रणभेरी बजने के एक सप्ताह में ही कुछ ऐसा दिखने लगा कि कल तक सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाली कांग्रेस 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है। पार्टी के रणनी. तिकार व नेता जोर खूब लगा रहे हैं परंतु मन ही मन में वर्तमान सत्तारूढ़ दल भाजपा को वाकओवर देने का मन बना चुके दिखने लगे हैं। इसके पीछे मुद्दों के अकाल के साथ–साथ पुलवामा के बाद भारतीय वायुसेना की एयरस्ट्राईक, राहुल गांधी के नेतृत्व आदि कारणों को माना जा सकता है। पार्टी के रणनीति वर्तमान चुनावों में अपने खोए हुए जनाधार को हासिल करने व अगले आम चुनाव में पूरी तैयारी से मैदान में उतरने की तैयारी की लगती है।

कर्नाटक में पिछड़ने के बावजूद भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखने और वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में मिली सफलता से एक बार लगने लगा था कि आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है। राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों और राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए हमलों के चलते वे पिछले पांच सालों में पहली बार विपक्ष के नेता दिखने लगे परंतु सर्वोच्च न्यायालय के साथ–साथ सार्वजनिक स्तर पर सरकार की रणनीति ने राहुल के राजनीतिक राफेल को तारपीड़ो कर दिया। बसपा, सपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी सहित अनेक क्षत्रप कहने को तो मोदी विरोध के नाम पर महागठबंधन की बात चलाते रहे परंतु लगता है कि इन क्षेत्रीय ताकतों को भी उस कांग्रेस का उभार पसंद नहीं आया जिसके विरोध में ही इनका जन्म हुआ। सभी जानते हैं कि बसपा कांग्रेस के दलित वोट बैंक की खाद–पानी पर ही पली बढ़ी और सपा व टीडीपी कांग्रेस विरोध के नाम पर अस्तित्व में आई। ममता ने कांग्रेस से निकल कर तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया। अगर कांग्रेस का पुनरोत्थान होता है तो स्वाभाविक है कि यह इन क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक मौत का ही पैगाम होगा। दूसरी ओर क्षत्रपों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं हो सकता जो अभी तक न तो इतने अनुभवी हैं और जिन्होंने अभी अपनी नेतृत्व कुशलता का प्रमाण भी नहीं दिया है। कांग्रेस का अहंकार व क्षत्रपों की असुरक्षा की भावना से महागठजोड़ की घटाएं बिना बरसे ही छंट गईं। सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, श्आपश् से तो ना मिल चुकी है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से भी बात बिगड़ती दिखाई देने लगी है। उधर टीडीपी ने भी कह दिया है कि वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ नहीं करेगी। अब महागठबंधन के गर्भपात और बालाकोट एयरस्ट्राईक के बाद कांग्रेस बदली हुई रणनीति पर काम करती दिखने लगी है।

कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि देश के बड़े भू–भाग जिसमें राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। इसीलिए यहां महागठबंधन का उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

यूपी, बंगाल, दिल्ली और बिहार में भी उसे महागठबंधन के कोटे से इतनी कम सीटें मिल रही हैं कि जो शर्मनाक तो है ही साथ में अगर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े तो भी वह महागठबंधन के नाम पर खैरात में मिलने वाली सीटों से अधिक सीटें हासिल कर सकती है। साथ में इन बड़े राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने से इन प्रदेशों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचे को भी राजनीतिक शक्ति मिलेगी जो निरंतर पराजयों व तरह–तरह के गठबंधनों के चलते लगभग खत्म–सा हो चुका है। बिहार, बंगाल, यूपी में कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को खड़ा कर लेती है तो 2024 की राह उसके लिए अत्यंत आसान हो सकती है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपने आखिरी तुरुप के पत्ते प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रिय तो कर चुकी है परंतु उन्हें अभी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। कुछ समय पहले तक समझा जा रहा था कि सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने के चलते अबकी बार रायबरेली से प्रियंका को उतारा जा सकता है परंतु पार्टी को ऐन वक्त पर अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और प्रियंका को केवल प्रचार अभियान तक सीमित कर दिया। पार्टी नहीं चाहती कि इन परिस्थितियों में प्रियंका पर दांव लगाया जाए क्योंकि आशंका है कि इसके वांछित परिणाम नहीं निकले तो पार्टी नेतृत्व शून्य सी हो सकती है। पार्टी की बदली हुई रणनीति के पीछे राहुल गांधी को भी माना जा रहा है, जिसे पार्टी कल तक मोदी का विकल्प बता रही थी वे हाल ही के दिनों में हकलान का शिकार होते दिखने लगे हैं। पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राईक के बाद की परिस्थितियों से राहुल गांधी जिस तरीके निपटे उसे एड़ी उठा कर गले में फंदा डालना ही कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है क्योंकि पुलवामा हमले के बाद न जाने किसके कहने पर उन्होंने गुजरात में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को स्थगित किया। असल में ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर तो राष्ट्रीय दल विशेष बैठकें करके सरकार को अपने फैसलों से प्रभावित करते और अपने काडर को उक्त मुद्दों पर पार्टी लाईन से अवगत करवाते हैं। पुलवामा हमले के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक को स्थगित न करके बैठक में सरकार को आतंकवाद पर हुई चूक पर घेरा जा सकता था। सरकार की तर्कसंगत आलोचना की जाती तो संभव है कि पार्टी के मुंहफटों को अपनी–अपनी लाईन पर चलने की स्वच्छंदता भी न मिलती और पार्टी किरकिरी से बच जाती। लेकिन गलत रणनीतिकारों के पीछे चल कर राहुल गांधी ने गुड़ गोबर कर दिया। देश में मतदान का पहला चरण पूरा होने में आज एक महीने से भी कम का समय रहा है परंतु महागबंधन तो दूर छोटे–छोटे दलों से तालमेल बैठाने में भी कांग्रेस को पसीने छूटते दिख रहे हैं। कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी नए पुराने 29 दलों से चुनावी गठजोड़ कर चुकी है और प्रचार में कहीं आगे है। इसके विप. रीत कांग्रेस की तैयारियों से लगने लगा है कि शायद वह 2024 के लिए दंड पेल रही है।

हमेशा अपनी सादगी और कर्मठता के लिए याद किये जाएंगे मनोहर पर्रिकर

2017 विधानसभा चुनाव के बाद गोवा में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने इस शर्त पर भाजपा को समर्थन दिया था कि मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद उन्हें देश के रक्षामंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर गोवा में भेजा गया। मनोहर पर्रिकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोवा में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुँचाया इसके साथ ही गोवा में भाजपा को एक अहम् पहचान दिलाई। मनो. हर पर्रिकर ऐसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो हमेशा सादगी से रहना पसंद करते थे। हमेशा आधे बाजू की शर्ट और स्लीपर में नजर आने वाले मनोहर पर्रिकर के चेहरे पर हमेशा मुस्कराहट भरी भाव भंगिमा रहती थी। वह अपने काम के प्रति समर्पित और लोगों के प्रति जवाबदेह व्यक्ति थे, उनकी यही खासियत उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग बनाती थी। वह भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आईआईटी से स्नातक किया। मनोहर पर्रिकर ने 1978 में आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। गोवा में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मनोहर पर्रिकर को जाता है। उनकी सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की वजह से ही वो गोवा के चार बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अंतिम सांस भी गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए ली। मनोहर पर्रिकर ऐसे नेता थे जिन्होंने गोवा में भाजपा की जड़ें जमाईं। गोवा में मनोहर पर्रिकर का नेतृत्व सर्वस्वीकार्य था। 2017 में गोवा में भाजपा को कांग्रेस से कम सीटें मिली फिर भी भाजपा ने मनोहर पर्रिकर के करिश्माई नेतृत्व की वजह से गोवा में पुनः सरकार बनाई और मनोहर पर्रिकर गोवा के चौथी बार मुख्यमंत्री बने, पर्रिकर ने गोवा में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद गोवा में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने इस शर्त पर भाजपा को समर्थन दिया था कि मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके बाद उन्हें देश के रक्षामंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर गोवा में भेजा गया। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, पारदर्शी, और स्पष्टवादी सोच मनोहर पर्रिकर को सबसे अलग बनाती थी, उनकी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, पारदर्शी, और स्पष्टवादी सोच कि बदौलत ही 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया। उन्होंने तीन साल तक देश के रक्षामंत्री के तौर पर अविस्मरणीय काम किया। उरी आतंकी हमले के बाद उन्होंने सेना द्वारा पकिस्तान में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक में भी अपनी एक अहम् भूमिका निभाई। कहा जाए तो रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने का काम किया। मनोहर पर्रिकर हमेशा विचारधारा पर अडिग रहने वाले और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। पिछले एक साल से वह अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे, कैंसर जैसी बीमारी की पीड़ा झेलते हुए भी लगातार एक साल से गोवा के लोगों की सेवा में समर्पित थे। कुछ समय पहले गोवा का बजट पेश करने से पहले मनो. हर पर्रिकर ने कहा था, श्परिस्थितियां ऐसी हैं कि विस्तृत बजट पेश नहीं कर सकता लेकिन मैं बहुत ज्यादा जोश और पूरी तरह होश में हूं।श इससे उनकी काम के प्रति भूख और परिश्रम का अंदाजा लगाया जा सकता है। मनोहर पर्रिकर ने अपने अंतिम समय तक पूरे जोश के साथ गोवा के लोगों और देशवा. सिओं की सेवा की। अपने अंतिम समय तक गोवा के लोगों की सेवा करने वाले, 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद पकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा की गयी सर्जिकल स्ट्राइक में देश के रक्षामंत्री के तौर पर अहम् भूमिका निभाने वाले, ईमानदारी, सादगी और समर्पण की मिसाल गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर का 63 साल की उम्र में आज (17 मार्च 2019) को दुखद निधन हो गया, उनका जाना भाजपा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राजनीतिक जगत के लिए क्षति है।

सभी से लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान की अपीलः ललित ठुकराल

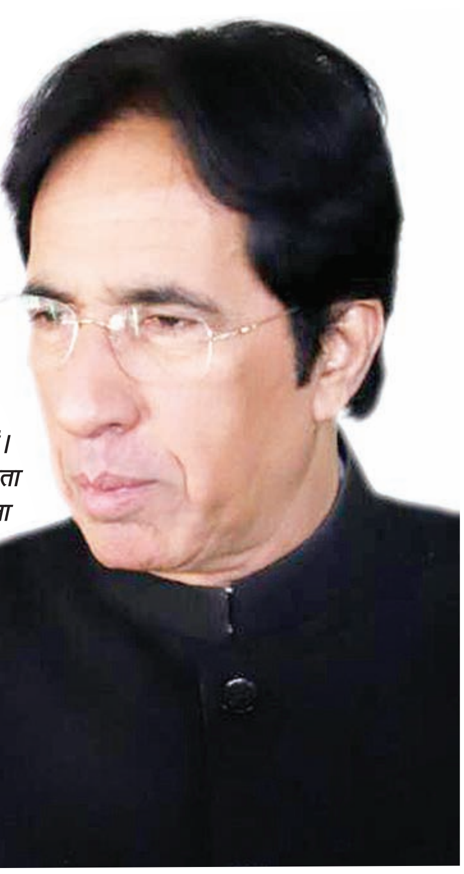

गौतमबुद्धनगर। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर मतदाता को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आपका वोट आपकी ताकत है। इसे व्यर्थ न करें। जागरूक मतदाता बनें व अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। यदि आपको अपना अच्छा नेता चुनना है तो आपका मतदान करना आवश्यक है। राष्ट्रहित में हर व्यक्ति को मतदान की शपथ लेनी चाहिए। कृपया करके नोटा का इस्तेमाल न करें एवं योग्य प्रत्याशी को मत देकर मत का सदुपयोग करें।

अपैरल पार्क बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगाः ललित ठुकराल

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल का दर्जा दिलवाने में डॉ. महेश शर्मा एवं उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री का उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति प्रबल है। रेडिमेड गारमेन्ट्स इंडस्ट्रीज से वर्तमान में नोएडा से 18,000 करोड़ रूपए का एक्सपोर्ट होता है, जोकि पूरे भारतवर्ष का 16 प्रतिशत है। अपैरल पार्क बन जाने से एक्सपोर्ट 10 हजार करोड़ रूपए का और बढ़ जाएगा। लगभग पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा तीन लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस तरह लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जिसमें से 70 प्रतिशत अकेले महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यह उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें अंगूठा छाप भी अच्छी नौकरी कर पायेगा। अपैरल पार्क के आसपास के गांवों में कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। जिनमें गांव के नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर उन्हें अपैरल पार्क में कम से कम 10 हजार रूपए की नौकरी मिलेगी और वे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। इस तरह आसपास के गांवों के हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिटी ऑफ अपैरल का बहुत बड़ा फायदा है। हम इस सिटी के सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। अब तक हमने यहां 6 इंडिया इंटरनेशनल गारमेन्ट्स फेयर के शो किए हैं। जिसमें देश–विदेश के हजारों आयातकों एवं निर्यातकों ने भाग लिया था। फेयर का उद्घाटन डॉ. महेश शर्मा ने ही किया है। रेडीमेट गारमेन्ट्स की ढाई हजार यूनिट नोएडा में है। यह इंडस्ट्री कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाली इंडस्ट्री है।

पृष्ठ तीन का शेष भाग

गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर सीट पर भाजपा पहले पायदान पर

जनता को यह भी मालूम हो रहा है कि आज देश सशक्त हो रहा है तथा विदेशों में भी हमारी धाक जम रही है। आज अंतरिक्ष में सैन्य उपग्रह माइक्रोसैट को एसैट मिसाइल से नष्ट करके भारत ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक को सटीक तरीके से दो बार इस तरह अंजाम दिया गया कि पाकिस्तान हाथ मलता रह गया। इससे सरकार की कार्यशैली एवं कार्य क्षमता का अंदाजा जनता लगा चुकी है। इसी का नतीजा है कि दोनों वीआईपी सीटों के मतदाता पहले से ही भाजपा को जिताने का मन बनाकर बैठे हुए हैं। यह बात उद्योग विहार द्वारा करवाए गए सर्वे में स्पष्ट रूप से उभरकर आई है।

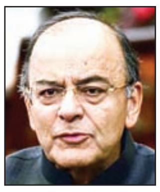

''कांग्रेस के इसके पहले के कर्जमाफी के वादे आज तक अधूरे रह गए हैं और इससे पुख्ता तौर पर साबित होता है कि कांग्रेस कैसी झांसेबाज है।''

अरूण जेटली, केंद्रीय वित्त मंत्री

''कांग्रेस को बखूबी पता है कि वह जीतने की स्थिति में नहीं है और राष्ट्रीय अफसाना उसके हाथ से फिसल गया है। इसलिए न्याय योजना उथल–पुथल मचाने की पुख्ता रणनीति है क्योंकि उसे पता है कि इस वादे को पूरा करने की नौबत नहीं आने वाली।''

भानू शिशौदिया, सांसद प्रतिनिधि गाजियाबाद

''अब तक का चुनावी इतिहास यही है कि गरीबों के लिए हर सकारात्मक नीति की घोषणा उस पार्टी को जीत दिलाने में कारगर होती है।''

सुखदेव थोराट, अर्थशास्त्री

कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और झूठ की बुनियाद पर कोई राजनीति नहीं होती है। मोदी के नए भारत का उदय हो गया है। क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तथा अपैरल पार्क एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सरकार पिछली सरकारों की बोई गई खराब फसल को काट रही है। लगभग 84 हजार फ्लैटों पर बिल्डरों से कब्जे दिलवाए गए हैं। पहली बार इस सरकार में अवैध बिल्डरों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्यवाही की गई है तथा रेरा का भी गठन इस सरकार के द्वारा बायर्स के हित में किया गया है।

—धीरेन्द्र सिंह (एमएलए, जेवर)

जनरल वी.के.सिंह ने 42 साल सेना में रहते हुए देश की सेवा की है तथा अब राजनीति में आकर देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। देश की जनता इस समय देश की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो गई है। क्यांकि उसे मालूम है कि उसका देश सुरक्षित हाथों में है। गाजियाबाद में मेट्रो, एलिवेटेड रोड़, हवाई अड्डा, रेपिड रेल और मेरठ एक्सप्रेस–वे जनरल वी.के. सिंह द्वारा करवाए गए ऐसे कार्य हैं जिसकी जनता भूरी–भूरी प्रशंसा कर रही है। देश के सारे चोर उचक्के बेइमान इस समय एक हो गए हैं। देश को इनसे बचाने के लिए जनता को मोदी ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहे हैं।

—नरेन्द्र शिशौदिया (पूर्व विधायक व सांसद प्रतिनिधि)

जनता इस समय प्रत्याशी से अधिक नरेंद्र मोदी को वरीयता दे रही है। क्योंकि जनता को यह मालूम है कि देश नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है। सारी गद्दार पार्टियां एक हो चुकी हैं तथा यह बात कांग्रेस ने अपने घोषणा–पत्र में साबित कर दी है कि उसने देशद्रोह कानून को खत्म करने की घोषणा की है। जनरल वी.के. सिंह ने जहां गाजियाबाद का विकास किया है, वहीं विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालकर लाने का असंभव कार्य भी किया है। यही कारण है कि इनको संकटमोचक के नाम से भी जाना जाने लगा है। जनता को नोटा का विरोध करना चाहिए तथा इस धर्म युद्ध में धर्म का साथ देने वाले को विजयी बनाना चाहिए।

—डॉ. मधु पोद्दार

डूब सकते हैं पीएफ-पेंशन खाते में जमा 20 हजार करोड़

दिवालिया होने के कगार पर है कंपनियां जिसमें लगा है पैसा

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। आपके पीएफ और पेंशन खातों पर बड़ी चपत लगने जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 20 हजार करोड़ का झटका ऐसे लोगों को लगने जा रहा है, जिनका पीएफ और पेंशन फंड का खाता खुला हुआ है।

यह है बड़ी वजह

आपके पीएफ और पेंशन फंड खाते का ज्यादातर पैसा कर्ज के बोझ तले इंक्रा कंपनी आईएलएंडएफएस में निवेश किया गया है। कंपनी फिलहाल दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में सैलरी क्लास वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक फंड मैनेजरों ने ज्यादातर पैसा बांड अथवा लोन के तौर पर कंपनी को दे रखा है। यह पैसा तब दिया गया था जब आईएलएंडएफएस की हालत काफी सही थी और इसको सुरक्षित निवेश के लिए ट्रिपल ए (एएए) की रेटिंग मिली हुई थी।

91 हजार करोड़ की देनदारी

कंपनी पर फिलहाल 91 हजार करोड़ की देनदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से जुड़ी सरकारी क्षेत्र की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) अपने कर्जों की किस्त नहीं चुका पा रही है। इसके चलते न केवल कई बड़े बैंक संकट में पड़ गए हैं बल्कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में पैसा लगाने वाले आम लोगों की मेहनत की कमाई भी दांव पर लगी है।

169 कंपनियों का समूह है आईएलएंडएफएस

2017–18 के आंकड़ों के अनुसार, आईएलएंडएफएस समूह में 169 कंपनियां हैं, इनमें आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी कंपनी लिमिलटेड आदि शामिल हैं।

40 प्रतिशत पैसा जाएगा डूब

आईएलएंडएफएस में निवेशकों के मुताबिक 40 फीसदी पैसा पेंशन और पीएफ खाते का जमा है। बाकी 60 फीसदी रकम यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लोन के तौर पर दिया गया था।

देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी गिरकर 26 फीसदी हुईः रिपोर्ट

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। रिपोर्ट में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कम होने का कारण गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच का अभाव और आर्थिक एवं सामाजिक बंधन को बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया, ''एशिया और भारत में महिलाओं एवं लड़कियों के समक्ष मुख्य चुनौतियां शिक्षा की कमी, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता का अभाव और डिजिटल विभाजन हैं जो उन्हें रोजगार योग्य कौशल पाने, श्रम बल में शामिल होने और उद्यम शुरू करने से रोकते हैं.श्श् डिलॉयट ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और रानजीतिक रुकावटों से महिलाओं के लिये अवसर कम होते हैं. रिपोर्ट में भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा और पुनः कौशल प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया. रिपोर्ट में चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में कहा गया, ''प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण और स्वचालन के उभार के दौर में यह आशंका प्रबल हो जाती है कि कम कौशल और कम वेतन वाले कार्यों में मुख्य तौर पर लगी अधिकांश महिलाओं का रोजगार प्रभावित होगा.''

पृष्ठ एक का शेष

फर्जी खबरों के बारे में आगाह करेगा वाट्सएप

टिपलाइन को भ्रामक पोस्ट या खबर के बारे में मैसेज कर सकेंगे। वाट्सएप यूजर की ओर से संदिग्ध मैसेज की जानकारी मिलते ही प्रोटो की टीम उस मैसेज के बारे में पड़ताल करेगी। इसके बाद यूजर को बताया जाएगा कि मैसेज में दी गई जानकारी सही है, गलत है, गुमराह करने वाली है, विवादित है या विषय से बाहर की है। साथ ही उसके बारे में उपलब्ध अन्य जानकारियों से भी यूजर को अवगत कराया जाएगा।

हर तरह के कंटेंट पर रहेगी नजर

यह सेंटर तस्वीर, वीडियो लिंक या टेक्स्ट के रूप में आने वाली सभी पोस्ट की समीक्षा करने में सक्षम है। इसमें अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषा में आने वाले पोस्ट को भी जांचा जा सकेगा। प्रोटो इस दिशा में देशभर में जमीनी स्तर पर काम रहे संगठनों के साथ मिलकर काम करने की दिशा में भी प्रयासरत है।

उठाए हैं और भी कदम

पिछले साल वाट्सएप पर फैली अफवाहों के कारण हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद भारत सरकार ने वाट्सएप की मूल कंपनी फेसबुक के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। अफवाहों और फर्जी खबरों पर लगाम कसने के बढ़ते दबाव के बीच वाट्सएप ने पिछले साल मैसेज फॉरवर्ड करने की सीमा घटा दी थी। अब एक बार में एक साथ अधिकतम पांच लोगों को ही मैसेज भेजा जा सकता है। वाट्सएप ने लोगों को जागरूक करने के लिए टीवी, अखबार और रेडियो पर विज्ञापन भी दिया है।

सरकार भी दिखा रही है सख्ती

सोशल मीडिया के जरिये बढ़ती अफवाहों पर नकेल के लिए सरकार भी सख्ती बरत रही है। सरकार ने गलत तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के मामले सामने आने पर सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करने को कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) को लेकर सरकार के प्रस्तावित नियमों में भी सोशल मीडिया को ज्यादा जवाबदेह बनाने की बात है। इसमें यह प्रावधान भी है कि जांच के समय सरकारी एजेंसियों की मांग पर सोशल मीडिया कंपनियां फर्जी मैसेज भेजने वालों की पहचान साझा करें। हालांकि वाट्सएप ने इस प्रावधान का यह कहते हुए विरोध किया है कि इससे एंड–टू–एंड एनक्रिप्शन कमजोर होगा।

तीन तलाक को अपराध बनाने वाला अध्यादेश बना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल के एक संगठन द्वारा इस संबंध में दाखिल की गयी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीठ इस मामले में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करेगी। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश को पहली बार पिछले साल 19 सितंबर को अधिसूचित किया गया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी थी। तीन तलाक जिसे 'तलाक–ए–बिद्दत' के रूप में भी जाना जाता है, एक त्वरित तलाक है, जिसके तहत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार श्तलाकश शब्द बोलते हुए तलाक दे सकता है। इस प्रथा को दंडनीय बनाने वाला अध्यादेश 21 फरवरी को तीसरी बार पारित किया गया था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर चुका है। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहा. सिक फैसले में मुस्लिम समुदाय में 1400 सालों से चल रहे तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) के प्रचलन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 5 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत (3:2)

के आधार पर दिए गए इस फैसले में कहा था कि तीन तलाक साफ तौर पर मनमाना है क्योंकि इसके तहत मुस्लिम पुरुष वैवाहिक संबंधों को खत्म करने की इजाजत देता है वह भी संबंध को बचाने का प्रयास करने के बगैर। लिहाजा संविधान के अनुच्छेद–25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इस प्रथा को संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस कूरियन जोसफ, जस्टिस रोहिंग्टन एफ. नरीमन और जस्टिस यू. यू. ललित ने जहां तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था तो वहीं तत्कालीन चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने ट्रिपल तलाक को अनुच्छेद–25 का अहम हिस्सा बताया। इनका कहना था कि 1400 वर्षों से चली आ रही प्रथा अब धर्म का हिस्सा बन गई है। जस्टिस कूरियन जोसफ ने अपने फैसले में कहा था कि तीन तलाक इस्लाम धर्म का मूल तत्व नहीं है। यह कुरान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा 'कुरान में जिस पर पाबंदी है, शर्रियत में उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। धर्मशास्त्र में जो जिस पर पाबंदी है और कानून की नजर में वह अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि तीन तलाक प्रथा शर्रियत के भी खिलाफ है। चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर के नजरिए से उलट जस्टिस जोसफ ने कहा कि महज इसलिए कि कोई प्रथा 1400 वर्षों से चली आ रही है उसे अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं जस्टिस रोहिंग्टन एफ. नरीमन और जस्टिस यू. यू. ललित ने अपने फैसले में कहा था कि अगर मुस्लिम महिलाएं न्याय के लिए अदालत के पास आए तो कोर्ट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा कि पति–पत्नी के संबंधों को सुधारने का प्रयास किए बिना एक झटके में तीन तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध को तोडना भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

वैवाहिक संबंध के टूटने से पहले दोनों परिवारों के बीच मध्यस्थता का प्रयास जरूरी है। वहीं चीफ जस्टिस जे. एस. खेहर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने अपने फैसले में तीन तलाक को संविधान के अनुच्छेद–25 का हिस्सा बताया था। साथ ही कहा था कि यह अनुच्छेद–14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता। हालांकि इन्होंने इस मसले को विधायिका के पाले में डाल दिया और कहा था कि सरकार 6 महीने में इसे लेकर कानून बनाए तब तक तीन तलाक पर रोक रहेगी। संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला शायरा बानो, इशरत जहां सहित 5 मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर याचिका पर दिया था। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला आदि को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था।

पृष्ठ एक का शेष

ईएसआई अस्पताल को 30 नए चिकित्सक मिलेंगे

इन डॉक्टरों को एक साल से अधिक अवधि पर नहीं रखा जा सकता था, जिसके चलते हर साल नए डॉक्टरों को रखना पड़ता था। नियमित डॉक्टरों की टीम बनने से चिकित्सीय सुविधाओं में काफी सहूलियत होगी। नियमित डॉक्टर श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। डॉक्टरों की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। 32 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र भेजे गए हैं, जिनमें से 25 डॉक्टरों ने काम करने को लेकर सहमति दे दी है। 29 मार्च को 30 डॉक्टरों के प्रभार संभालने की उम्मीद है। 29 मार्च के बाद अस्पताल में पेट, हड्डी, कान, आंख, हार्ट से संबंधी कई बीमारियों के इलाज कराने वाले मरीजों को अच्छी सलाह और सुविधाएं मुहैया हो सकेगी।

इन्द्रधनुष (एक सुरमयी शाम)

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)
गाजियाबाद। 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन यू.पी. द्वारा आयोजित कार्यक्रम इन्द्रधनुष (एक सुरमयी शाम) में लोगों ने भारत वर्ष के विभिन्न प्रदेशों के नृत्य का आनन्द लिया जिसे सबरंग ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तथा सुष्मिता घोष बासू ने अपनी नृत्य प्रस्तुति से लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि लोग अपनी कुर्सियों से चिपक कर बैठे रहे। कार्यक्रम में एसोसिएशन के कई सदस्यों के बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्घाटन एन ए ई सी के अध्यक्ष ललित ठुकराल ने दीप प्रज्ज्वलन करके किया। कार्यक्रम का संचालन कवियत्री डॉ. अल्पना सुहासिनी ने किया। कार्यक्रम में पी एफ विभाग, श्रम विभाग के कई अधिकारीयों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का इवेन्ट मैनेजमेंट 'तक्षक मैनेजमेंट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड' एवं उत्थान समिति द्वारा किया गया।

संबंधित फोटो पृष्ठ आठ पर

इन्द्रधनुष (एक सुरमयी शाम)

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
(EVENTS, PR & ARTISTS MANAGEMENT)

Address : -

The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002,

Moblie : 9818036460, 9818697406

info@takshindia.com, takshakindia@gmail.com, www.takshakindia.com

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह

दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

यूवी इंडिया न्यूज

उद्योग विहार समाचार-पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादकः सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▸ अंक : 4 ▸ गाजियाबाद, अप्रैल, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

फर्श से अर्श तक
जवाहर लाल मोंगा.. P-4

निवेश मित्र पोर्टल पर प्रदूषण विभाग की सर्वाधिक शिकायतें लंबित

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

गाजियाबाद। उद्यमियों को अलग–अलग विभागों के आफिस और पोर्टल पर प्रार्थना पत्र और समस्याएं अपलोड करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल लागू किया गया। अपलोड प्रपत्र के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। लंबित शिकायतों को देखे तो कई विभाग पोर्टल को लेकर निष्क्रिय नजर आते हैं। मौजूदा समय में प्रदूषण विभाग से संबंधित करीब 141 शिकायतें लंबित हैं। दूसरी नंबर पर फूड सेफ्टी और तीसरे पर फायर सर्विस विभाग है।

❑ अपलोड प्रपत्र के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। लंबित शिकायतों को देखे तो कई विभाग पोर्टल को लेकर निष्क्रिय नजर आते हैं। मौजूदा समय में प्रदूषण विभाग से संबंधित करीब 141 शिकायतें लंबित हैं।

वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, जिसे जनहित गारंटी एक्ट में शामिल किया गया है। गत 30 जून 2018 के बाद इस पोर्टल में 20 विभागों की 70 ऑनलाइन सेवाएं शामिल की गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची दी गई है। प्रदेश में व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के लिए निवेश मित्र पोर्टल लागू किया, जिसमें उद्यमी आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अपने आवेदन, समेकित शुल्क भुगतान और पोर्टल में डाली गई प्रार्थना व शिकायत स्थिति की निगरानी कर सकता है। इसमें 20 विभागों की 70 ऑनलाइन सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमे समस सीमा में तमाम प्रक्रियाओं के निस्तारण का प्रावधान है। ऐसा न करने वाले विभाग अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश हैं। लेकिन यहां स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। पोर्टल पर कई विभाग पूरी तरह निष्क्रिय हैं। पोर्टल की मौजूदा स्थिति पर नजर डाले पिछले दिनों जनपद में 2065 प्रार्थना पत्र अपलोड किए गए, जिनमें 1112 को सुनवाई के लिए चुना गया। इनमें 243 को जांच के बाद रिजेक्ट कर दिया। सर्वाधिक मामले प्रदूषण विभाग से संबंधित थे। प्रदूषण विभाग के पोर्टल पर पड़ी 561 प्रार्थना पत्रों में 420 उद्यमियों की ओर से कमियां सीमा बीत जाने के बावजूद 141 प्रार्थना पत्र अभी तक विभागीय स्तर से लंबित हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर फूड सेफ्टी विभाग हैं, जिसके पोर्टल पर नौ शिकायतें लंबित हैं और तीसरे नंबर पर फायर सर्विस है, जिसकी आठ लंबित चल रही हैं। इसके अलावा यूपीएसआइडीसी की तीन व बाट माप विभाग की तीन शिकायतें लंबित हैं।

ईपीएस पेंशन बढ़वाने के लिए आपको क्या करना होगा

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के बाद ईपीएफओ को फरवरी में जारी अपना सर्कुलर वापस लेना होगा तथा जनवरी के सर्कुलर को बहाल करना होगा। इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों को अंशदान बढ़ाने के इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार करने और बढ़ी पेंशन देने का आदेश दिया गया था।

इसके अलावा, ईपीएफओ को अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पूरे अंतिम वेतन के हिसाब से ईपीएस पेंशन की गणना करनी होगी। इसके लिए कर्मचारी को कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यदि कोई कर्मचारी 8.33 से अधिक अंशदान देकर पेंशन में और वृद्धि चाहता है तो इसके लिए अवश्य उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में आवेदन देना होगा। जो कर्मचारी अभी नौकरी में हैं, उन्हें अंशदान बढ़वाने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति से आवेदन देना होगा। परंतु सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधे आवेदन दे सकते हैं। आवेदन में कर्मचारी को ये बात लिखकर देनी होगी कि वो अपना अंशदान बढ़वाना चाहता है।

ईपीएफ और ईपीएस के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी के वेतन में से 12 प्रतिशत ईपीएफ के लिए कटता है। इतना ही योगदान नियोक्ता को भी करना होता। नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस में जाता है। कर्मचारी का वेतन कितना भी हो लेकिन 2014 के संशोधन

❑ ईपीएस पेंशन 58 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है।

❑ नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की दशा में विधवा पत्नी को आजीवन अथवा दूसरी शादी तक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दो बच्चों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है।

❑ नौकरी के दौरान विकलांग होने पर कर्मचारी आजीवन पूरी पेंशन का हकदार है।

❑ कर्मचारी चाहे तो 50 वर्ष की आयु के बाद कभी भी पेंशन का दावा कर सकता है। परंतु 58 वर्ष की आयु तक उसकी पेंशन में हर साल 4 प्रतिशत की कमी होगी।

के अनुसार ईपीएस के लिए कटौती केवल 15,000 रुपये तक के वेतन पर होती है। इससे ईपीएस में अधिकतम अंशदान केवल 1250 रुपये महीने का होता है। ईपीएस एक्ट में 1996 में हुए संशोधन और उस पर 2016 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर्मचारी चाहे अपने अंशदान को वेतन (मूल व महंगाई भत्ता समेत) के 8.33 प्रतिशत से बढ़वाकर अधिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। हालांकि इससे नियोक्ता का अंशदान नहीं बढ़ता है। फिर भी कर्मचारी को अपना अंशदान बढ़वाने के लिए उसकी मंजूरी हासिल करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ईपीएफओ किसी भी कर्मचारी का अंशदान बढ़ाने का अनुरोध अस्वीकार नहीं कर सकता। यहां तक कि सेवा. निवृत्त कर्मचारी भी अपना कुछ पीएफ ईपीएफओ को वापस देकर और 1996 या नियुक्ति की तारीख से अंशदान बढ़ाने का आवेदन देकर बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे होती है पेंशन की गणना

मान लें कि आपने 1996 में नौकरी शुरू की। उस समय वेतन 6000 रुपये मासिक था। इसमें सालाना आठ प्रतिशत के हिसाब से वेतन वृद्धि हुई। आप 33 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हुए तो आपका अंतिम वेतन लगभग 50 हजार रुपये होगा। और सालाना 8.5 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से ईपीएस कोष में आपका कुल योगदान लगभग 12.93 लाख रुपये का हो चुका होगा।

इसके बावजूद चूंकि आपसे केवल 15,000 रुपये पर अंशदान लिया जाएगा लिहाजा आपको केवल 5,182 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद 25 वर्ष जीते हैं तो इस हिसाब से ईपीएस से आपको केवल 1.52 प्रतिशत रिटर्न हासिल होगा। दूसरी ओर, यदि ईपीएस में आपका 8.33 प्रतिशत अंशदान पूरे वेतन से काटा जाए तो आपको 25 हजार रुपये की पेंशन के हिसाब से 11–12 प्रतिशत रिटर्न हासिल होगा।

पिछले पांच साल में चमत्कारिक रही भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति

वाशिंगटन। पिछले पांच साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति चमत्कारिक रही है। इस प्रगति के दम पर अगले पांच साल में भारत पांच लाख करोड़ डॉलर (करीब 350 लाख करोड़ रूपये) की अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह बात कही। अभी भारती अर्थव्यवस्था करीब पौने तीन लाख करोड़ डॉलर की है।

अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ मिलकर भारतीय उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रृंगला ने भारत को सबसे मजबूत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से बताया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई की दर पांच साल पहले के 10 फीसद तुलना में घटकर 4.6 फीसद पर आ गई है। राजकोषीय घाटा करीब छह फीसद से घटकर तीन फीसद पर आ गया है।

ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। उन्होंने कहा, 'हमने पिछले पांच साल में व्यापक प्रगति है। हमने जिस तरह से विकास किया है, वह चमत्कारिक है। महंगाई अपने आप में मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के लिए किसी टैक्स जैसी होती है। महंगाई और राजकोषीय घाटा को कम रखना अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रशासन व प्रबंधन का नतीजा है।'

वादों के पिटारे में हकीकत खोजते कॉरपोरेट सेक्टर

पांच साल पहले जिन लोकलुभावन वादों के साथ सरकार का आगाज हुआ था, अंजाम वैसा नहीं रहा। योजनाओं पर काम तो हुआ, पर उनकी गति इतनी धीमी रही कि कई योजनाओं को लागू करने में पांच वर्ष भी कम पड़ गए। कोई शक नहीं है कि योजनाओं की दिशा सटीक थी, लेकिन केवल फाइलों में कागजों की मुंह देखती इन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल सका। अब चुनावी मौसम में एक तरफ अधूरे वादों को पूरा करने की सोच है तो दूसरी तरफ नये वादों की लंबी सूची। ऐसे में कॉरपोरेट सेक्टर दुविधा में है कि मौजूदा सरकार के साथ जाए या किसी और बेहतर विकल्प के लिए जमीन तैयार करे।

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

बदला कंपनियों का माहौलः उद्योग. विहार स्थित एक कंपनी में माहौल में बदलाव दिख रहा है। जहां कॉरपोरेट कल्चर में काम के समय काम की नीति अपनाई जाती है वहां लोग अपनी–अपनी डेस्क से डायलॉग डिलिवर करते नजर आए। अपने–अपने सिस्टम में नजरें गड़ाए तो कभी किसी बात पर पलटकर जवाब देते युवाओं के तेवर साफ बता रहे थे कि कंपनियों में चुनावी हलचल का असर पड़ा है और युवाओं की सोच में बदलाव आ रहा है। अप्रैल की शुरूआत जहां क्लोजिंग के बाद नई शुरूआत, कंपनी की नई नीतियों और हानि लाभ पर केंद्रित चर्चा का समय होता है वहां लोग मोदी, राहुल, प्रियंका की बातें करते नजर आ रहे थे। केवल कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी भी अपने विचार रखते। कैंटीन में पॉलिटिकल शोरगुल है तो कंपनियों के बाहर युवतियां फैशन और डाइटिंग की जगह आने वाली सरकार से विकास, बदलाव, सुरक्षा की उम्मीद में बेहतर नेतृत्व पर चर्चा कर रही हैं।

पटी सरकार और कॉरपोरेट की बीच की खाई : जेस्चर रीचर्स टेक्नोलॉजीज के निदेशक मुनीष धीमान कहते हैं कि मौजूदा सरकार आने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में काफी सकारात्मक बदलाव आए जिससे बिजनेस के लिए राहें आसान हुई हैं। अब सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच की खाई पट गई है। सिस्टम के ऑनलाइन हो जाने से कई औपचारिकताएं बेहद आसान और पारदर्शी हो गई हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। कॉरपोरेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि भावनाओं में बहने से ज्यादा विश्वास हकीकत की जमीन पर टिके रहने में दिखाता है। यहां का युवा किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय के प्रभाव में न आकर केवल बेहतर नेतृत्व का चुनाव करना चाहता है। युवा महसूस कर रहे हैं कि सरकार की आलोचना बहुत हुई है लेकिन इस सेक्टर से जुड़े युवाओं को लगता है कि कई योजनाओं के लाभ भी मिले हैं। जीएसटी के विरोध में लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन सच यह है कि उससे कॉरपोरेट सेक्टर की राहें बहुत आसान हो गई। अब वन मिशन वन टैक्स के साथ राज्य टैक्स की परेशान हल हो गई है। इसी तरह की छोटी कंपनियों में नवोदित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सरकार इस क्षेत्र में काफी अग्रेसिव सोच रख रही है उनसे पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर मांगा जाता था जबकि अब ऐसी बाध्यताएं नहीं हैं। स्टार्टअप के लिए ऋण दिए जाएंगे। इस घोषणा का स्वरूप ऐसा बनाया गया था कि लगा जैसे किसी को भी दस लाख रूपये का ऋण मिल जाएगा लेकिन जब लोगों ने इसका लाभ लेना चाहा तो उन्हें नहीं मिल सका। इसका कारण यह था कि इस योजना के तहत ऋण पाने की इतनी शर्तें व पेपर वर्क था कि इसका लाभ किसी को नहीं मिल सका।

इसलिए आइटी हब बना गुरूग्राम : समय के साथ–साथ स्थान की कमी व व्यवसाय के नियमों के कारण दिल्ली से कंपनियां बाहर हो गई। विकल्प के तौर पर प्रगति के सूरज की चमक ओढ़ता गुरूग्राम एक ग्लोबल हब बन गया। चूंकि भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीन इकोनॉमी में से एक है। ऐसे में निवेशक यहां पर आकर्षित हो रहे हैं। जमीन, कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की छमता को देखते हुए कंपनियां यहां आने लगीं। लिकर, शूज, अपैरल, ऑटोमोबाइल जैसी कंपनियों ने पिछले दस वर्षों में गुरूग्राम में अपनी कंपनियां खोलीं जो कि शहर की बड़ी उपलब्धि है। पहले यहां केवल मर्सेडीज की कपंनी थी लेकिन गुरूग्राम बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वॉल्वो, एमजी मोटर्स जैसी कंपनियां आईं।

कारपोरेट सेक्टर का स्वरूप

- –पांच हजार से अधिक कॉरपोरेट कंपिनयां
- –दस लाख से अधिक लोगों को सीधा और 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया करवा रही हैं
- –दस सालों में आइटी हब बना गुरूग्राम
- –देश का तकरीबन पैंतालीस प्रतिशत विदेशी निवेश गुरूग्राम में

यह चाहिए

- –टैक्सेशन के नियम कानून की प्रक्रिया का सरलीकरण
- –निजीकरण को बढ़ावा
- –इस सेक्टर को लेकर योजजनाएं प्रक्रियाएं व्यवस्थित होना चाहिए
- –विदेशी निवेश के नियमों को आंकलन करना चाहिए
- –इंवेस्टर फ्रेंडली नीतियां बनाई जानी चाहिए
- –सरकार को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए

अब निजी क्षेत्र के कर्मी भी अच्छी पेंशन पायेंगे

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निजी कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए पहले से ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ईपीएफओ) द्वारा केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष याचिका को खारिज कर दिया है। इससे देश भर के निजी क्षेत्रों के करोड़ों कर्मचारियों को इस मंहगाई के दौर में राहत मिलेगी। इससे श्रमजीवी पत्रकार भी लाभान्वित होंगे। केरल उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ से कहा था कि वह सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पूरी तनख्वाह के आधार पर पेंशन दे ना कि अंशदान के आधार पर तय किया जाए जोकि प्रतिमाह अधिकतम 15 हजार रूपये निर्धारित है। अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें विशेष याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। इसी वजह से इसे खारिज किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के पेंशन में भारी बढ़त का रास्ता साफ कर दिया है। इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन में कई गुना बढ़त हो जाएगी।कोर्ट ने इस मामले में ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट फैसले को बरकरार रखा है। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आद. ेश दिया गया था। फिलहाल ईपीएफओ द्वारा 15,000 रुपये के बेसिक वेतन की सीमा के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है।

गौरतलब है कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 12 फीसदी हिस्सा पीएफ में जाता है और 12 फीसदी उसके नाम से नियोक्ता जमा करता है।कंपनी की 12 फीसदी हिस्सेदारी में 8.33 फीसदा हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.66 पीएफ में। उच्चतम न्यायालय ने अब यह रास्ता साफ कर दिया है कि निजी कर्मचारियों के पेंशन की गणना पूरे वेतन के आधार पर हो। इससे कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। ईपीएफ या ईपीएस एक पेंशन स्कीम है, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी के दौरान बेसिक सेलरी के 8.33 फीसदी (1250 रुपए मासिक से ज्यादा नहीं) के बराबर पैसा इस स्कीम में जमा होता है। इसके एवज में, यह कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित घ्मासिक पेंशन प्रदान करती है। भारत सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ही सभी कर्मचारियों के ईपीएफ और पेंशन खाते को मैनेज करता है। हर ऐसा संस्थान जहां पर 20 या इससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उसे ईपीएफ में हिस्सा लेना होता है। ईपीएस इस योजना के साथ जुड़कर चलती है इसलिए ईपीएफ स्कीम का मेंबर बनने वाला हर शख्स पेंशन स्कीम का मेंबर अपने आप बन जाता है।

ईपीएफ या ईपीएस में, ऐसे कर्मचारियों का अंशदान जमा होना अनिवार्य है, जिनका बेसिक वेतन. डीए 15000 रुपये या इससे अधिक होता है। जो कर्मचारी इससे अधिक बेसिक सैलरी पाते हैं, उनके पास ईपीएफ और म्च्े को अपनाने या छोड़ने का विकल्प होता है। आपके पीएफ खाते में नियोक्ता जो पैसा डालता है उसका एक हिस्सा पेंशन स्कीम के लिए ही इस्तेमाल होता है, जबकि आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है वो पूरा का पूरा ईपीएफ स्कीम में चला जाता है। तो अगर पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन बनी तो कर्मचारियों का पेंशन कई गुना बढ़ जाएगा। इसमें नुकसान बस इतना है कि पेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन पेंशन फंड की निधि कम हो जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त योगदान ईपीएफ में जाने की जगह ईपीएस में जाएगा। केंद्र सरकार ने ईपीएस की शुरुआत 1995 में की थी। इसके तहत नियोक्ता कर्मचारी के 6,500 तक के मूल वेतन का 8.33 फीसदी हिस्सा (अधिध्कतम 541 रुपये प्रति महीना) पेंशन स्कीम में डालने का नियम था। लेकिन 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफओ ने इसमें बदलाव करते हुए 15,000 तक के मूल वेतन का 8.33 फीसदी (अधिकतम 1,250 रुपये प्रति महीना) कर दिया. सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन और पीएफ की व्यवस्था जीपीएफ के तहत होती है। मार्च 1996 में सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। जिसके अनुसार यदि कर्मचारी अपनी पूरी तनख्वाह के हिसाब से योजना में योगदान देना चाहे और नियोक्ता भी इसके लिए राजी हो तो उसे पेंशन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। सितंबर 2014 में ईपीएफओ ने एक बार फिर से नियम में बदलाव किया। जिसके बाद अधिकतम 15 हजार रुपये के 8.33 फीसदी के योगदान को मंजूरी मिल गई।

हालांकि इसके साथ यह नियम भी लाया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी पूरी तनख्वाह पर पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन वाली तनख्वाह पांच साल के हिसाब से तय की जाएगी। इससे पहले यह पिछले साल की औसत तनख्वाह पर तय होता था। जिसके कारण कई कर्मचारियों की तनख्वाह कम हो गई थी। फिर मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। जिसके बाद केरल उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2014 को हुए बदलाव को रद्द करके पुरानी प्रणाली को बहाल कर दिया था।

अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया था फैसला

अक्टूबर, 2016 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि कर्मचारी को पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का अधिकार है और इसके लिए कोई कट ऑफ डेट तय नहीं की जा सकती है। इसके आधार पर 12 रिटायर्ड कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर ईपीएफओ से ज्घ्यादा पेंशन की मांग की थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ईपीएफओ को इन कर्मचारियों को हायर कंट्रीब्घ्यूशन जमा कराने पर ज्घ्यादा पेंशन देने का आदेश दिया था। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी हायर पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में हीलाहवाली कर रहे थे।

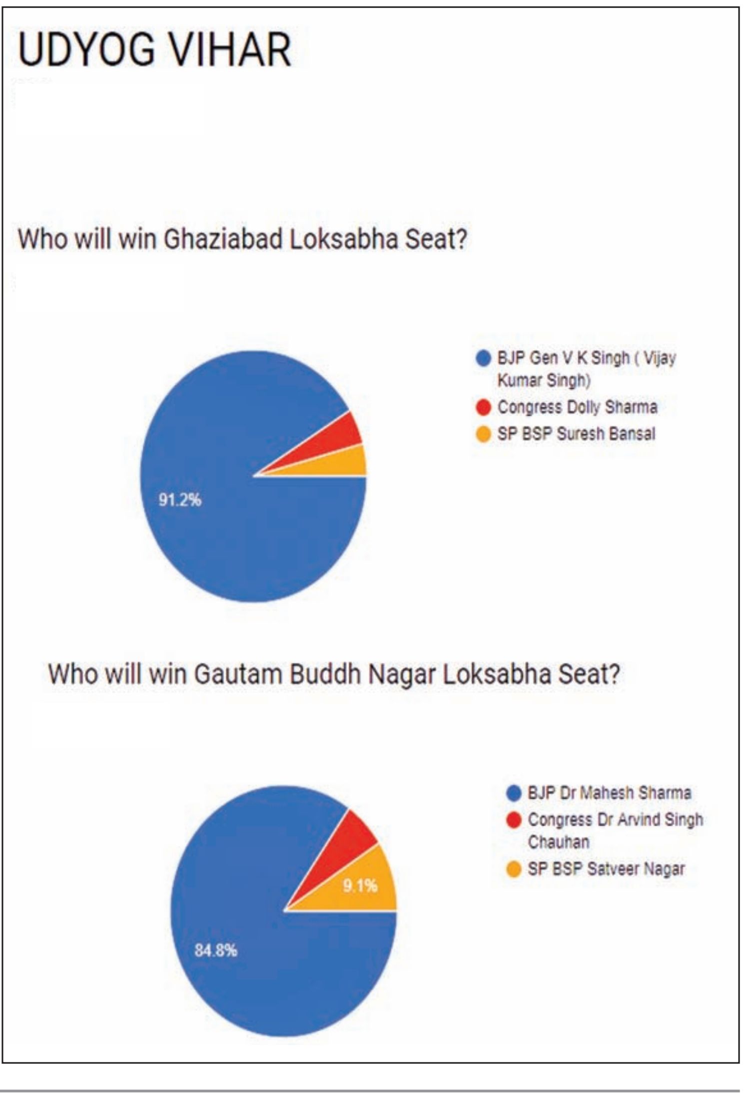

यूवी इंडिया न्यूज
उद्योग विहार समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, अप्रैल, 2019

ध्वनि प्रदूषण गंभीर अपराध

मापदंड से ज्यादा ध्वनि पैदा करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीर अपराध करार दिया है। एनजीटी ने पुलिस से कहा है कि निर्धारित मापदंड से ज्यादा ध्वनि पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस आयुक्त को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। पीठ ने इस पर एक महीने के भीतर ई–मेल के जरिये रिपोर्ट भी तलब की है।

❑ शांत वातावरण में रहना लोगों का संवैधानिक अधिकार

❑ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसे माना गंभीर अपराध

एनजीटी ने कहा है कि शांतिपूर्ण वातावरण में रहना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। तय मानकों से ज्यादा शोर पैदा करना गंभीर अपराध है, इसको रोकने के लिए निरोधात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत है।

पीठ ने अखंड भारत मोर्चा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि पूर्वी दिल्ली में मस्जिदों में अवैध तरीके से लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से उसके आस–पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

पीठ ने कहा कि अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले स्थलों की पहचान, वहां ध्वनि मापक यंत्र लगाने और तय स्तर से ज्यादा ध्वनि पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। पीठ ने यह भी कहा कि समय–समय पर जांच और निगरानी की व्यवस्था होने के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ समन्वय भी होते रहना चाहिए।

एनजीटी ने कहा कि जब बड़े स्तर पर कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पत्र लिख देने मात्र से काम नहीं चलने वाला।

छोटे उद्योगों को अब ज्यादा रियायतें देगी सरकार

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

लखनऊ। सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने, बाजार की प्रतिस्पर्धा और निर्यात के लायक बनाने के लिए सरकार उन्हें प्लांट व मशीनरी की खरीद और इसकी खातिर लिये गए लोन पर अदा किये जाने वाले ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए ज्यादा सब्सिडी देगी। इन इकाइयों को प्रमाणीकरण संस्थाओं से सर्टिफिकेट आदि प्राप्त करने, कंसल्टेंसी हासिल करने और उत्पादों की ब्रांडिंग पर होने वाले खर्च के लिए भी सरकार अनुदान देगी। इसके लिए वर्ष 2007 में लागू की गई तकनीकी उन्नयन योना को नए कलेवर में ढाला गया है। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। नई योजना के तहत सूक्ष्म श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को 7.5 लाख और लघु इकाइयों को 15 लाख रूपये तक की रियायतें व प्रोत्साहन मिल सकेंगे। सरकार तीन साल से अधिक अवधि से संचालित सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाइयों को प्लांट मशीनरी और उपकरण खरीदने पर 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रूपये होगी। पुरानी योजना के तहत दो लाख रूपये की सीमा तक ही कैपिटल सब्सिडी देने की व्यवस्था थी। मशीनें और उपकरण खरीदे के लिए बैंकों से कर्ज लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को अदा किये जाने वाले ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति की जाएगी। उद्यमी द्वारा तकनीकी उन्नयन के लिए तैयार की गई कार्ययोजना पर बैंक द्वारा दिये गए ऋण में से कैपिटल सब्सिडी की राशि घटाते हुए बची हुई धनराशि पर अदा किये जाने वाले ब्याज का 50 फीसद सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

ईपीएफओ अधिकारी 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। सीबीआई ने प्रवर्तन अधिकारी ईपीएफओ को 50 हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्रवर्तन अधिकारी पिछले सात साल के हिसाब से तीन लाख 50 हजार रूपये मांग रहा था, लेकिन बाद में तीन लाख देना तय हुआ। 50 हजार रूपये रिश्वत की पहली किश्त थी।

सीबीआई का कहना है कि गिरफ्तार अधिकारी का नाम एबी पहाड़े है। इन दिनों वह नागपुर में तैनात हैं। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि नागपुर स्थित एक फर्म विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को श्रमिक मुहैया कराती है। इसके लिए यह पीएफ विभाग में अपना शेयर भी जमा करा रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले प्रवर्तन अधिकारी एबी पहाड़े ने अपने स्टाफ के साथ फर्म के कार्यालय में निरीक्षण किया।

इस दौरान दस्तावेजों में कमी पाई गई, लेकिन फर्म के अधिकारियों ने गत पांच सालों के दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी को मुहैया करा दिए। प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि वह पीएफ कार्यालय में आकर मिलें क्योंकि उनका पेंडिग पीएफ ऑडिट की जांच की जाएगी।

रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को दौसा जिले के थाना अधिकारी के रीडर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि थाना अधिकारी के रीडर आरोपी कांस्टेबल धरम सिंह ने दुष्कर्म के एक आरोपी से दुष्कर्म मामले की भादंसं की धारा 376 को हटाने के लिए 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में मामले में 40 हजार रुपए की सहमति बनी और आरोपी कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

सरकारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा, छह साल में दो करोड़ लोग हुए बेरोजगार

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2011–12 से लेकर वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान पांच साल में देश में पुरुष कार्यबल में करीब दो करोड़ की कमी आई. एनएसएस की इस रिपोर्ट को हाल ही में सरकार ने दबा दिया. एनएसएसओ की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2017–18 की समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 2017–18 के दौरान सिर्फ 28.6 करोड़ पुरुष देश में रोजगार में थे जबकि 2011–12 में 30.4 करोड़ पुरुष रोजगार में थे. यह समीक्षा अभी सार्वजनिक नहीं हुई है.

भारत का पुरुष कार्यबल 1993–94 में 21.9 करोड़ था, जिसके बाद पहली बार इसमें कमी दर्ज की गई है. पुरुष कार्यबल 2011–12 दौरान बढ़कर 30.4 करोड़ हो गया जबकि 2017–18 में घटकर 28.6 करोड़ रह गया. पीएलएफएस की रिपोर्ट जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के बीच तैयार की गई.

एनईए ने दी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि

उद्योग विहार (अप्रैल–2019)

नोएडा। नोएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) ने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सेक्टर–6 स्थित एनईए सभागार में किया। इस मौके पर एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने बताया कि मनोहर परिकर एक ईमानदार, कर्मठ, अनुशासन प्रिय, सच्चे देश भक्त एवं सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। इस तरह के महापुरूष काफी लम्बे समय बाद पैदा होते हैं। वहीं, देश ने एक विशाल राजनेता को खो दिया है। वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इस मौके पर एनईए महासचिव वीके सेठ, उपाध्यक्ष सुधीर श्रीवातस्व, मोहन सिंह, कमल कुमार, पियूष मंगला, नीरू शर्मा, आरएम जिंदल, विजय कत्याल समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।

यूवी इंडिया न्यूज
उद्योग विहार समाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, अप्रैल, 2019

फर्श से अर्श तक

जवाहर लाल मोंगा

परिचयः जवाहर लाल मोंगा

हर सिक्के के दो पहलू होते है लेकिन अक्सर हम सिक्के के एक ही पहलू को देख पाते है. आज हम आपके साथ फैशन इंडस्ट्री के ऐसे ही शख्स के सफर के बारे में बताने जा रहे है जिन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष के साथ अपनी जिन्दगी की शुरुआत की और सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रखा. वे लगातार कड़ी मेहनत करते रहे और (सफलता) के मुकाम तक पहुँच गए।

आपने फिल्मों में तो सुना होगा कि हीरो कैसे फर्श से अर्श तक पहुँचता है और फिल्म का हीरो बनता है। अबकी बार हम आपको एक ऐसे ही शख्स से रूबरू करवा रहे हैं जिनका नाम जवाहर लाल मोंगा है वे ''सॉल्टी'' के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनका ब्रांड 'सुलक्षणा मोंगा' फैशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हैं। उनसे उद्योग विहार के मुख्य संपादक सत्येन्द्र सिंह के साथ बातचीत के कुछ अंश आपको प्रस्तुत हैं।

- आर्थिक तंगी की वजह से इनको अपनी पढाई पत्राचार के माध्यम से पूरी करनी पड़ी।
- मैंने लाल किले में दशहरे के अवसर पर मौत के कुएँ में मोटर साइकिल भी चलाई जिसके एवज में मुझे 200 रुपए मिल जाते थे।
- हौज खास में मारवाड़ीज के नाम से बुटीक खोला हमारा सबसे पहला बुटीक हौजखास में था।
- ब्रांड सुलक्षणा मोंगा फैशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हैं।
- हर व्यक्ति के अन्दर अर्जुन छुपा हुआ है, उसे सिर्फ कृष्ण मिलना चाहिए।
- हमारा शो-रूम ही एक ऐसा अकेला शो रूम है जिसके स्टोर की फ्रेंचाइजी लंदन में भी है।
- हमारे कपड़ों को उर्वशी रौतेला, अदिति राव हैदरी, दिव्या खोसला कुमार, भूषण कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, चित्रांगना सिंह, इलियाना डिक्रूज आदि कई लोग बड़े शौक से पहनते हैं।
- हमने जीनियस फिल्म भी बनाई थी जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा थे जिन्होंने गदर, अपने, हीरो, श्रद्धांजलि, हुकूमत, इत्यादि मशहूर फिल्मों को डायरेक्ट किया है।

जवाहर लाल ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस के साथ हर मुसीबत को हराते हुए निरन्तर आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इनका जन्म दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी की वजह से इनको अपनी पढाई पत्राचार के माध्यम से पूरी करनी पड़ी। और अपनी पढाई का खर्चा भी इन्होंने स्वयं उठाया था। इनके दो बेटे हैं बड़ा बेटा पोरस एवं छोटा बेटा ध्रुव जो की माँ के साथ बिजनेस में हाथ बटाते हैं। ध्रुव एक नामचीन फैशन डिजाइनर में शुमार है।

आपने अपने जीवन के शुरूआती दौर में कैसे संघर्ष किया? कृपया बताएं ?

मैंने अपनी पढाई इण्टर के बाद छोड़ने के बजाय पत्राचार के माध्यम से की क्योंकि हम आर्थिक तंगी में थे। जबकि मैंने 1979 में जब सी बी एस सी का बोर्ड शुरू हुआ था मै पहले बैच का छात्र था जिसने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। मैंने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली लेकिन पैसों की वजह से मेडिकल नहीं कर सका फिर मैं साइकिल से सदर बाजार से पेन, पेंसिल और किताबें खरीद कर दुकानों में सप्लाई करने लगा और धीरे धीरे मैंने 1980 दिसंबर में एक मोटर साइकिल खरीदी और उससे अपना व्यापार करता रहा। मैंने लाल किले में दशहरे के अवसर पर मौत के कुएँ में मोटर साइकिल भी चलाई जिसके एवज में मुझे 200 रूपये मिल जाते थे।

क्या आपको खेलों का भी शौक था, जो आपने मौत के कुएँ जैसा खतरनाक खेल चुना? फिर व्यापार को कैसे जमाया ?

पैसों के लिए हमने खतरों से खेला। मैंने 1979 में दिल्ली से अंडर 19 क्रिकेट भी खेला था। लेकिन व्यापार फिर जमने लगा था और किताबों का काम स्कूलों से भी मिलने लगा और हमने कई बड़े स्कूलों के अन्दर ही अपनी दुकानें खोल लीं। जैसे डी पी एस, ए पी जे, हमदर्द, और कई नामचीन स्कूलों के साथ मैंने काम किया है।

आप किताबों के व्यापार से फैशन जगत में कैसे आये ?

मेरा परिचय जब सुलक्षणा मोंगा से हुआ जब वे 16 साल की थी तब मैंने उनकी क्रिएटिविटी को देखा और उनसे प्रभावित हुआ वे मारवाड़ी खानदान से थीं और बहुत ही संकोची स्वभाव की थी लेकिन उनके अन्दर एक महान कलाकार था जिसको मै पहचान चुका था। 1987 में हमारी उनसे शादी हुई फिर मैंने उनकी इस क्रिएटिविटी को उभार कर उसे फैशन की दुनिया से जोड़ा और हौज खास में मारवाड़ीज के नाम से बुटीक खोला हमारा सबसे पहला बुटीक हौजखास में था। उस समय भारत के प्रथम 5 बुटीक में एक हमारा भी था। उसके बाद सिग्नेचर (थॉमसन प्रेस), एवं OGAIN (शोभना भरतिया की बेटी का) बुटीक हमें देख कर ही खुला था। इसके बाद वहाँ पर कई मार्केट डेवलप हुई। हर व्यक्ति के अन्दर अर्जुन छुपा हुआ है, उसे सिर्फ कृष्ण मिलना चाहिए। मैंने उनको रास्ता दिखाया और तीर उन्होंने चलाया।

आप नोएडा कब आये और क्या आपके शो-रूम भी हैं ?

मै 2003 में नोएडा आया था उस समय यहाँ पर कोई भी डिजाइनर नहीं था मै यहाँ पर सबसे पहले आया था फिर और भी डिजाइनर को यहाँ पर लाया और आज नोएडा में सर्वाधिक डिजाइनर हैं और यह फैशन इंडस्ट्री का हब बन चुका है। आज हमारी कम्पनी में लगभग 550-600 आदमी काम करते हैं और हमारा एक शो-रूम दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने मेहरौली में है। इसके अलावा मुंबई में गेट वे ऑफ इण्डिया के सामने, लुधियाना में सरभा नगर में, और यू के में बर्मिंघम में हैं। हमारा शो-रूम ही एक ऐसा अकेला शो रूम है जिसके स्टोर की फ्रेंचाइजी लंदन में भी है।

आपके कपड़े क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी पहनते हैं? आपके फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सम्बन्ध हैं?

हाँ, हमारे कपड़े फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े स्टार पहनते है। बॉलीवुड और फैशन का रिश्ता भाई बहन का अटूट रिश्ता है। हमारे कपड़ों को उर्वशी रौतेला, अदिति राव हैदरी, दिव्या खोसला कुमार, भूषण कुमार, सिद्दार्थ मल्होत्रा, उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, चित्रांगना सिंह, इलियाना डिक्रूज, आदि कई लोग बड़े शौक से पहनते हैं। हमने जीनियस फिल्म भी बनाई थी जिसके डायरेक्टर अनिल शर्मा थे जिन्होंने गदर, अपने, हीरो, श्रद्धांजलि, हुकूमत, इत्यादि मशहूर फिल्मों को डायरेक्ट किया है। जीनियस में अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा हीरो थे उनको इस फिल्म से लॉन्च किया गया है। प्रियंका चोपड़ा को आगे बढ़ाने में अनिल शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है और इनके साथ हमारे पारिवारिक सम्बन्ध हैं।

आप सामाजिक कार्य भी बहुत करते रहते हैं कुछ कार्यों के विषय में प्रकाश डालिये ?

मैं अनाथालय एवं अंध विद्यालय के बच्चों की पढाई लिखाई का खर्चा उठाता हूँ और अभाव ग्रस्त बच्चों की बचपन की पढाई से लेकर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने तक आत्मनिर्भर बनाता हूँ और उनके लिए रोजगार भी पैदा करता हूँ। हमने अपनी जिन्दगी बहुत अभाव में देखी है और हमें मालूम है की किसी बच्चे को अपने पैरों पर तभी खड़ा किया जा सकता है जब वह पढ़ा लिखा हो इसलिए पढाई का जीवन में बहुत महत्व है। इसके साथ ही सफाई अभियान से भी मै जुड़ा हुआ हूँ।